
इकाई 6 अनिश्चितता में नीति निर्माण

इकाई की रूपरेखा

- 6.0 उद्देश्य
- 6.1 भूमिका
- 6.2 लुकास के अर्थमिति नीति मूल्यांकन की समीक्षा
- 6.3 लुकास की समीक्षा का महत्व
 - 6.3.1 लघु आधार
 - 6.3.2 विवेकपूर्ण प्रत्याशाएं एवं नीति नियम
 - 6.3.3 कुछ अनिवार्यताएँ
- 6.4 नियम बनाम स्वनिर्णय
- 6.5 सारांश
- 6.6 महत्वपूर्ण शब्द
- 6.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें
- 6.8 बोध प्रश्नों के उत्तर/संकेत

6.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आप जानने की स्थिति में होंगे:

- लुकास की समीक्षा के औचित्य की व्याख्या;
- लुकास की समीक्षा के निहितार्थों को;
- लुकास की समीक्षा के महत्व की व्याख्या; और
- समष्टिगत आर्थिक मॉडलों के व्यक्तिगत आर्थिक आधारों की आवश्यकता की व्याख्या।

6.1 भूमिका

अर्थशास्त्र के अधिकांश स्नातकस्तरीय पाठ्यक्रमों में सरकारी नीति के प्रभाव का अध्ययन मुख्य रूप से एक ही बार में सभी नीति प्राचलों (policy parameters) में परिवर्तन के रूप में जो परम्परागत केंसीय समष्टिगत आर्थिक मॉडल जैसे IS-LM मॉडल में सन्निहित हैं, किया जाता है। 1970 के दशक से ही प्रत्याशा के निर्माण में विवेकपूर्ण प्रत्याशा की पूर्व संकल्पना का प्रयोग होने लगा व धीरे-धीरे इसकी स्वीकार्यता बढ़ने लगी। इस मुद्दे पर चर्चा बढ़ने लगी कि समष्टिगत आर्थिक सिद्धांत और समष्टिगत आर्थिक मॉडल की प्रकृति वैकल्पिक समष्टिगत आर्थिक नीतियों के उपयुक्त मूल्यांकन को किस प्रकार सरल बना सकती है अथवा उसे अवरुद्ध कर सकती है। रॉबर्ट लुकास ने नीति मूल्यांकन के अपर्याप्त आधार पर परम्परागत समष्टिगत आर्थिक मॉडल की आलोचना की जो इस विवेचना में मील का पत्थर थी। अतः इस खण्ड में हमारा अध्ययन भाग 6.2 में लुकास की आलोचना से आरम्भ होता है। चूंकि यह आलोचना

परम्परागत समष्टिगत आर्थिक सिद्धान्त की प्रकृति ओर उन्मुख थी, इसका समष्टिगत आर्थिक प्रविधि के लिए बहुत अधिक महत्त्व था – कि समष्टिगत आर्थिक मॉडल किस प्रकार बनाए जाने चाहिए। इसके पश्चात् भाग 6.3 में लुकास द्वारा की गई आलोचना के प्राविधिक महत्त्व, तदन्तर निर्मित समष्टिगत आर्थिक मॉडल की प्रकृति पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

इस आलोचना का एक महत्वपूर्ण निहितार्थ यह था कि नीति का मूल्यांकन नीतिगत चरों के मूल्य में केवल एक ही बार परिवर्तन के रूप में नहीं बल्कि नीतिगत नियमों के अंश के रूप में किया जाना चाहिए। नीतिगत नियम यह रूपरेखा प्रदान करते हैं कि किस प्रकार भावी नीति का निर्धारण किया जायेगा। नियम आधारित नीति की कुछ सुस्पष्ट लागतें हैं जो आकस्मिक घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करने की असफलता अथवा नियम में सन्निहित अशुद्ध गणना को शुद्ध करने के रूप में विद्यमान होती हैं। केवल नियमों के आधार पर बनायी गयी नीति की स्थिति में उसकी अविचारित आकस्मिक घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया में विफलता या नियम में पहले से उपस्थित गलत गणनाओं को सही करने में विफलता के रूप में काफी अधिक कमियाँ हैं। इसके बावजूद भी, इन नीति निर्माणक नियमों के पालन के समर्थन और विवेक पर आधारित नीति निर्माण पर रोक लगाने के विषय में कई अन्य तर्क दिए गए हैं। भाग 4 में इन तर्कों पर विचार किया गया है।

6.2 लुकास के अर्थमिति नीति मूल्यांकन की समीक्षा

केंस के सामान्य सिद्धांत ने अर्थशास्त्र की एक शाखा के रूप में समष्टिगत अर्थशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। परन्तु एक विषय के रूप में समष्टिगत अर्थशास्त्र का अध्ययन, विशेषकर संयुक्त राज्य में, कुछ गणितीय सूत्रीकरणों पर आधारित था। चाहे उचित हो या अनुचित, परन्तु यह केंस के आर्थिक सिद्धांत का सार माने गये। सरल केंसीय मॉडल, IS-LM और AS-AD मॉडल काफी लम्बे समय तक स्नातकस्तरीय समष्टिगत अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तकों के मूलाधार बने रहे। इन मॉडलों ने समष्टिगत अर्थमिति (econometrics) मॉडलों का उपयोग लक्षित समष्टिगत आर्थिक चरों पर वैकल्पिक नीतियों के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया¹। यद्यपि केंस ने स्वयं ही नीति मूल्यांकन के लिए इन मॉडलों के प्रयोग का विरोध किया था परन्तु 1960 के दशक के मध्य तक अधिकांश औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में समष्टिगत आर्थिक नीतियों में मॉडल का विभिन्न अंशों में उपयोग नीति निर्माण के लिए किया गया।

किसी भी समष्टिगत आर्थिक मॉडल में अर्थव्यवस्था की कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिन्हें स्थिर मान लिया जाता है। विशेषताओं के इस पूरे समूह जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे आर्थिक संरचना या मॉडल की संरचना कहा जाता है। संरचना को दर्शाने वाले संख्यात्मक स्थिरांक को संरचनात्मक प्राचल कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की वह विशेषताएं जिनमें परिवर्तन होता रहता है, मॉडल में उन्हें चर कहा जाता है। इन चरों को दो श्रेणियों: अन्तर्जात (endogeneous) और बहिर्जात (exogeneous) चरों में बांटा जा सकता है। अन्तर्जात चर वह चर हैं जिनकी व्याख्या मॉडल के अन्तर्गत की जाती है जबकि बहिर्जात चर वह चर हैं जिनका पहले से ही ज्ञात होना मान लिया जाता है तथा इनका निर्धारण मॉडल के बाहर होता है।

आइए, उदाहरण के लिए हम आय निर्धारण का निम्न सरल मॉडल लेते हैं:

1. समष्टिगत अर्थमिति मॉडल निर्माण के इतिहास में संभवतः दो व्यक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं—हालैंड के अर्थशास्त्री जेन टिबर्जन और अमेरिकी अर्थशास्त्री लारेंस क्लेन।

$$c + i = y \quad \dots (6.1)$$

$$c = a(1 - t)y + b \quad \dots (6.2)$$

जहाँ c : सकल वास्तविक उपभोग व्यय, i : सकल वास्तविक निवेश व्यय, y : वास्तविक आय और, t : राष्ट्रीय आय के अनुपात में प्रत्यक्ष करों से (वास्तविक) राजस्व (सरकारी हस्तांतरण आय को कम कीजिए) यहाँ a और b धनात्मक स्थिरांक ($0 < a, b < 1$) हैं जो संरचनात्मक प्राचल को दर्शाते हैं, c और y अन्तर्जात चर हैं तथा i और t बहिर्जात चर हैं। (6.2) समीकरण में हम कह सकते हैं कि $(1-t)y$ निजी उपभोज्य आय है।

उपरोक्त मॉडल एक निश्चयवादी (deterministic) मॉडल है जहाँ बहिर्जात चरों के मूल्यों के दिये होने पर अन्तर्जात चरों c और y को पूर्णतया निर्धारित किया जाता है। चूंकि दो अन्तर्जात चरों से सम्बंधित दो समीकरण दिये गये हैं जिससे हम c और y के संतुलन मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः समीकरण (6.1) और समीकरण (6.2) से हम पाते हैं,

$$y = (i + b) / \{1 - a(1 - t)\} \quad \dots (6.3)$$

$$c = \{a(1 - t)i + b\} / \{1 - a(1 - t)\} \quad \dots (6.4)$$

तथापि एक निर्धारक मॉडल का उपयोग प्रायः ब्याज के चरों के महत्वपूर्ण निर्धारक कारकों को अलग-अलग करने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में यह y है और यह मॉडल में चरों में पाये जाने वाले सम्बंधों को सरल और स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इसलिए ये मॉडल निश्चित रूप में, वास्तविकता का सरलीकृत प्रदर्शन करते हैं, जो ब्याज के चरों को प्रभावित कर सकने वाले 'प्रत्येक' कारक को अपने अंदर शामिल नहीं करते। अतः अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि (6.2) जैसे निर्धारक समीकरण अन्तर्जात (जैसे c और y) और बहिर्जात (जैसे i और t) चरों के बीच सम्बन्ध को सही प्रकार से नहीं दर्शाते जैसाकि वास्तविक आंकड़ों से पता चलता है।

निश्चयवादी आर्थिक मॉडलों का वास्तविक आंकड़ों से सम्बन्ध जोड़ने के लिए, सामान्य युक्ति यह है कि एक मॉडल के विभिन्न निर्धारक समीकरणों में भिन्न-भिन्न नये चरों का प्रयोग किया जाए। यह मान लिया जाता है कि नए चर प्रत्येक समीकरण में उन अन्य सभी कारकों के प्रभाव को उजागर कर देंगे, जो उस समीकरण में प्रस्तुत चरों के बीच वास्तविक सम्बन्ध को प्रभावित कर सकते हैं। मॉडल के प्रयोग में लाए जाने वाले चर दैव (random) चर हैं जो मॉडल के अन्तर्जात और बहिर्जात चरों के निर्धारणकारी सम्बन्ध में आने वाले आकस्मिक उतार चढ़ावों को दर्शाते हैं। इस प्रकार, (6.1)–(6.2) के निर्धारक को निम्न प्रकार रूपान्तरित किया जा सकता है:—

$$c + i = y \quad \dots (6.1)$$

$$c = a(1 - t)y + b + u \quad \dots (6.2')$$

जहाँ u समीकरण (6.2) द्वारा बताए गये वास्तविक सम्बन्ध में उतार-चढ़ाव लाने वाली एक अतिरिक्त इकाई को दर्शाता है। (6.2), जो एक निर्धारक समीकरण है की तुलना में (6.2') को हम सांयोगिक (stochastic) समीकरण कहते हैं क्योंकि इसमें एक सांयोगिक इकाई 'u' शामिल की गयी है। (6.1) में उतार चढ़ाव लाने वाली कोई इकाई शामिल नहीं की गयी, क्योंकि यह एक पारिभाषिक समानिका है।

समीकरण (6.1) और (6.2') एक बहुत सरल समष्टिगत अर्थमिति मॉडल को दर्शाते हैं, यदि सभी चरों की अवधि ज्ञात हो (अर्थात्, यह स्पष्ट हो कि क्या ये सभी चर समान

अवधि से सम्बन्धित हैं अथवा कुछ चरों के पिछले मूल्य लिये जाने चाहिए) और u के संभाव्यता वितरण के विषय में मान्यताएं निश्चित हों। नीति विश्लेषण के लिए वास्तविक अर्थव्यवस्थाओं द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले यथार्थ समष्टिगत अर्थमिति मॉडल कई चरों और समीकरणों को शामिल करने के कारण निःसंदेह अधिक विशाल होते हैं। उदाहरण के लिए 1955 में एल.आर.क्लेन और ए.एस. गोल्डबर्गर द्वारा संयुक्त राज्य के लिए विकसित प्रतिष्ठित समष्टिगत अर्थमिति मॉडल में भी 20 सांयोगिक समीकरण, 20 अन्तर्जात चर और 18 बहिर्जात चर थे।

ऊपर दर्शाए गए एक सरल आय-निर्धारण मॉडल में, हमने माना कि t एक नीति से सम्बंधित चर है। यदि हम यह मान लें कि दैव चर u का प्रत्याशित मान 0 है, तो (6.1) और (6.2) से, यह ज्ञात होता है कि y का प्रत्याशित मान (i और t के मूल्य ज्ञात होने पर) होगा—

$$E(y) = (i + b) / \{1 - a(1 - t)\}$$

किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय y के प्रत्याशित मान पर t के वैकल्पिक चुनावों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए (यह मानते हुए कि i पहले से ज्ञात है), अर्थव्यवस्था के लिए संरचनात्मक स्थिरांकों a और b के मूल्यों के संभावित अनुमानों को जानना आवश्यक है। ऐसा, मॉडल में चरों से सम्बंधित पूर्व आंकड़ों का उपयोग करके मॉडल (6.1)–(6.2') के स्थिरांकों का सांख्यिकीय गणन करके किया जा सकता है।

स्पष्ट रूप से कहा जाए तो, a की सांख्यिकीय गणना हमें समग्र उपभोग व्यय में होने वाले औसत परिवर्तन का अनुमानित मूल्य बताती है, जो पूर्वकाल में अर्थव्यवस्था में उपभोज्य आय में आए इकाई परिवर्तन से सम्बन्धित होता है। ध्यान दें कि उपभोग के सिद्धान्त जैसे कि जीवन चक्र या स्थायी आय सिद्धान्त (इकाई 7 में विचार किया जायेगा) यह पुष्टि करते हैं कि अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय न केवल वर्तमान उपभोज्य आय पर, वरन् उपभोज्य आय के भावी प्रत्याशित स्तरों पर भी निर्भर करता है। उपभोज्य आय के प्रत्याशित स्तर, t चर के भावी प्रत्याशित मूल्यों पर निर्भर करते हैं। अतः एक निश्चित परिस्थिति में उपभोग व्यय जिस रूप में कर की वर्तमान दरों और उपभोज्य आय में आए परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करता है, वह इस पर पूर्णतया निर्भर करता है कि कर की दरों के प्रत्याशित मूल्य तथा वर्तमान मूल्यों में परिवर्तन के साथ उपभोज्य आय किस प्रकार परिवर्तित होती है।

अतएव, एक निश्चित समयावधि के लिए आंकड़ों से प्राप्त a का सांख्यिकीय आकलन हमें बताता है कि किस प्रकार करों की दर में और उपभोज्य आय में परिवर्तन होने पर उपभोग व्यय में होने वाले परिवर्तन का अनुमान लगाया जा सकता है, परन्तु केवल उसी संदर्भ में, जब कर की दरों में हुआ वर्तमान परिवर्तन कर की दरों के भावी अनुमानों पर उसी प्रकार का प्रभाव डाले जिस प्रकार का प्रभाव उस अवधि में पड़ा था, जिस अवधि के आंकड़ें प्रयोग में लाए गए थे।

अब, मान लें कि पहले नीति सम्बन्धी वातावरण ऐसा रहा हो कि कर की दरों में होने वाले अधिकांश परिवर्तन स्वभावतः अस्थायी रहे हों। इस प्रकार के नीति सम्बन्धी वातावरण में, नीतिगत परिवर्तनों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए गृहस्थ अपनी प्रत्याशाओं को व्यवस्थित करेंगे। अतः वर्तमान कर की दरों में परिवर्तन का गृहस्थ द्वारा पहले इस प्रकार अनुमान किया गया कि इनका भावी प्रत्याशित कर की दरों पर कम प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार, उपभोज्य आय के भावी स्तरों में कम परिवर्तन आएगा अतएव, अर्थव्यवस्था में

गृहस्थों की स्थायी आय और उपभोग व्यय का इस प्रकार के नीति सम्बन्धी वातावरण में वर्तमान कर की दरों में परिवर्तन और उपभोज्य आय में परिवर्तन का कमजोर सम्बंध रहेगा। अतएव, a का अनुमानित मूल्य अपेक्षाकृत कम होगा।

फिर, मान लें, सरकार एक अधिक स्थायी कर नीति पर विचार करती है, जिसमें कर की दरों में होने वाले परिवर्तन अधिक स्थायी हैं। यदि अर्थव्यवस्था में गृहस्थ नीति सम्बन्धी वातावरण में इस परिवर्तन को समझें, तब वे मान लेंगे कि वर्तमान कर की दरों में आया कोई भी परिवर्तन, भावी कर की दरों के अनुमानित मूल्यों और उपभोज्य आय पर अच्छा खासा प्रभाव डालेगा। इस प्रकार वर्तमान कर की दरों में आया कोई भी परिवर्तन अर्थव्यवस्था में गृहस्थों की स्थायी आय और उपभोज्य व्यय के स्तरों पर गहरा प्रभाव छोड़ेगा। अतएव, यदि नीति निर्माता पूर्व आंकड़ों से प्राप्त a के सांख्यिकीय आकलन का प्रयोग करें, तब वे अर्थव्यवस्था में कर, नीति में परिवर्तनों के उपभोज्य व्यय और आय पर पड़ने वाले प्रभाव का कम आकलन करेंगे।

उपरोक्त प्रकार के अर्थमिति नीति मूल्यांकन में समस्या को कुछ विशिष्ट विशेषताओं को, जो ऊपर दिये गये अभ्यास में भी उपस्थित हैं, खोजा जा सकता है। पहला, नीति मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त समष्टिगत अर्थनीति मॉडल (हमारे उदाहरण में (6.1) और (6.2')) में विभिन्न सामूहिक चरों के व्यवहारों में सम्बन्ध स्थापित करने वाले समीकरण शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, (6.2') अर्थव्यवस्था के समग्र उपभोग व्यय का अर्थव्यवस्था की समग्र उपभोज्य आय से सम्बंध दिखलाता है। दूसरे, विभिन्न समग्र चरों के बीच पाये जाने वाले वास्तविक व्यवहारिक सम्बंध-अर्थव्यवस्था में विभिन्न व्यक्तिपरक एजेंटों (गृहस्थ, फर्म आदि) द्वारा लिये बहुत सारे निर्णयों का परिणाम है। अतः अर्थव्यवस्था में समग्र उपभोग व्यय और उपभोज्य आय के मध्य पाये जाने वाला सम्बंध विभिन्न गृहस्थों द्वारा लिये गये निजी उपभोग निर्णयों का परिणाम है। तीसरे, आर्थिक एजेंटों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर लिये गये निर्णयों की प्रकृति अन्तर्कालिक होती है। अर्थात् भावी उद्देश्यों और प्रतिबंधों को ध्यान में रखकर ही वर्तमान समय में निर्णय लिये जाते हैं। उदाहरण के लिए, वर्तमान उपभोग के बारे में निश्चय करते समय गृहस्थ उपभोग से व्युत्पन्न वर्तमान और भावी उपयोगिता के मध्य प्रतिस्थापन को ध्यान में रखना चाहेंगे और वर्तमान तथा भावी उपभोज्य आय दोनों को ध्यान में रखते हुये उपभोग की कुल सम्भावनाओं का मूल्यांकन करेंगे।

विभिन्न समग्र चरों के बीच सम्बंध इस पर निर्भर करते हैं कि, वर्तमान मूल्यों में परिवर्तन के साथ प्रत्याशित भावी मूल्य किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। विशेष बात यह है कि यह संबंध इस बात पर निर्भर करेंगे कि नीतिगत चरों के भावी मूल्यों की प्रत्याशाएं, नीतिगत चरों के वर्तमान मूल्यों में परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होती हैं। माना नीतिगत चरों के वर्तमान मूल्य में होने वाला समान परिवर्तन दो विभिन्न समय बिन्दुओं पर निजी आर्थिक कर्त्ताओं की नीतिगत चरों के भावी मूल्यों से सम्बंधित प्रत्याशा पर विभिन्न प्रभावों को प्रेरित करता है। तब भिन्न समय बिन्दुओं पर नीतिगत चरों और अन्य समग्र चरों सहित व्यवहारगत सम्बंध (behavioural relations) भिन्न होंगे।

निहितार्थ यह है कि व्यवहार समीकरणों के प्राचल जो मॉडल के ढांचे का एक अंग है, को समयावधि के दौरान एक समष्टिगत अर्थमिति मॉडल में स्थिर मान लिया गया है, परन्तु वास्तव में इन्हें स्थिर नहीं माना जा सकता। सार रूप में, यह नीति मूल्यांकन में लुकास की समष्टिगत अर्थमिति मॉडल के उपयोग की समीक्षा है।

अब हम पिछली इकाई में वर्णित मुद्रा स्फीति-बेरोजगार प्रतिस्थापन के द्वारा लूकास की समीक्षा की व्याख्या करते हैं। जब तक सरकार अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मांग के स्तर को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करती, मजदूर स्वीकार करते हैं कि सरकारी नीति के कारण अर्थव्यवस्था के मौद्रिक व्यय की वृद्धि दर में उतार-चढ़ावों की प्रकृति सांयोगिक है और मजदूर प्रत्याशा करते हैं कि मौद्रिक व्यय में औसत वृद्धि दर पूर्वकाल के समान बनी रहती है।

अतः श्रमिक मुद्रा स्फीति दरों की स्थिर प्रत्याशा करते हैं और बेरोजगारी में उतार-चढ़ाव और मुद्रा स्फीति की दर में वास्तविक उतार-चढ़ाव से सम्बंधित ऐतिहासिक आंकड़ों से एक फिलिप्स वक्र बनाते हैं।

अब यदि मजदूर यह विश्वास करते हैं कि नीति व्यवस्था की पद्धति में परिवर्तन हुआ है और यह कि सरकार योजनाबद्ध रूप से बेरोजगारी के प्राकृतिक दर से कम लक्ष्य को मानकर, उस सम्बन्ध को प्राप्त करना चाहती है, तो मजदूर भविष्य में मौद्रिक व्यय की एक ऊँची वृद्धि दर और मुद्रा स्फीति की एक ऊँची दर की प्रत्याशा करेंगे। परिणामस्वरूप, अब यदि विगत आंकड़ों के आकलन पर आधारित फिलिप्स वक्र के आधार पर यदि सरकार मुद्रा स्फीति की ऊँची दर का बेरोजगारी पर प्रभाव का अनुमान लगाने की कोशिश करे, तब सरकार बेरोजगारी पर इस नीति के प्रभाव का अधि-मूल्यांकन करेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि तब मजदूरों द्वारा प्रत्याशित मुद्रा स्फीति की दर, पूर्वकालिक नीति व्यवस्था के समय की मुद्रा स्फीति की दर से ऊँची होगी।

बोध प्रश्न 1

- 1) एक सरल सांयोगिक (stochastic) समष्टिगत अर्थमिति का उदाहरण दीजिए।

.....

- 2) लूकास द्वारा समष्टिगत अर्थमिति मॉडलों की, कि गयी प्रमुख आलोचना क्या है?

.....

6.3 लूकास की समीक्षा का महत्त्व

लूकास की समीक्षा का 1970 के उपरान्त समष्टिगत आर्थिक सिद्धान्त पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस समीक्षा के अनुसार, वैकल्पिक नीतियों के प्रभावों की जाँच करने के लिए उन समष्टिगत आर्थिक मॉडलों में अर्थनीति का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जिनमें स्पष्ट रूप से समष्टिगत चरों के बीच निश्चित व्यवहारिक सम्बन्धों को मान लिया है। वास्तविक समस्या यह है कि सम्पूर्ण नीतिगत वातावरण में एक रूप में परिवर्तन आने पर, इन व्यवहारिक समीकरणों के प्राचलों में नीति के अनुसार परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसा नहीं माना जा सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न नीति-व्यवस्था में व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों की प्रतिक्रिया नीति परिवर्तन के कारण भिन्न-भिन्न होती है।

6.3.1 लघु आधार

लुकास की समीक्षा के अनुसार, नीतियों का सही ढंग से मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है कि समष्टिगत आर्थिक मॉडलों में इस बात पर विचार किया जाए कि किस प्रकार नीति-व्यवस्था में भिन्नता से एक विशेष नीति के प्रति व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा तब ही किया जा सकता है यदि समष्टिगत आर्थिक मॉडलों में स्पष्ट मान्यताएं ली जाएँ कि किस प्रकार व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट अपने निर्णय लेते हैं (जिसमें यह भी शामिल है कि किस प्रकार सरकार की वर्तमान और भावी नीतियाँ उनकी नीति निर्माण प्रक्रियाओं में शामिल हो जाती हैं), उनकी (भावी सरकारी नीतियों सहित) भविष्य के प्रति प्रत्याशाएं कैसे निर्धारित होती हैं और किस प्रकार व्यक्तिगत एजेंट आपसी व्यवहार के माध्यम से अर्थव्यवस्था में समष्टिगत आर्थिक चरों के मूल्य निर्धारित करते हैं। मॉडल में सामूहिक चरों के मध्य कोई भी सम्बन्ध इन लघु आर्थिक मान्यताओं से प्राप्त होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, लुकास की समीक्षा यह कहती है कि प्रत्येक समष्टिगत आर्थिक मॉडल में लघु आधार (micro-foundations) समाहित होते हैं। इस पाठ्यक्रम के शेष भाग में, जिन समष्टिगत आर्थिक मॉडलों पर विचार किया गया है, उनमें से कई के स्पष्ट लघु आधार हैं।

लघु आधारों को शामिल करने का एक और तर्क है। IS-LM मॉडल जैसे परम्परागत समष्टिगत आर्थिक मॉडल में विभिन्न व्यवहारवादी सम्बंध जैसे समग्र उपभोग फलन, निवेश फलन और मुद्रा का मांग फलन समाहित होते हैं। परन्तु जिन अर्थशास्त्रियों ने इन मॉडलों का उपयोग किया है, लघु आर्थिक व्यवहार के संदर्भ में समष्टिगत आर्थिक चरों के बीच पाये जाने वाले माने गये व्यवहारवादी सम्बंधों को न्याय संगत ठहराया है। उदाहरण के लिए 1950 के दशक में विलियम बॉमल और जेम्स टाबिन ने केंस के मुद्रा के मांग फलन की व्याख्या का प्रयास अर्थव्यवस्था में लेन देन हेतु कोषों की मांग के माडल निर्माण से तथा जेम्स टाबिन ने भी इसी तरह का प्रयास अर्थव्यवस्था में सट्टेबाजी हेतु मुद्रा की मांग के मॉडल से किया है।¹

इस प्रकार किसी भी ऐसे परम्परागत समष्टिगत आर्थिक मॉडल के बारे में सोचा जा सकता है जिसके निर्माण में व्यक्तिगत आर्थिक मान्यताओं को लिया जाता है। परन्तु एक मॉडल में विभिन्न व्यावहारिक समीकरणों (जिन्हें संभवतः समय के विभिन्न बिन्दुओं पर, भिन्न-भिन्न अर्थशास्त्रियों ने स्वतन्त्र रूप से सिद्ध किया हो), अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत आर्थिक ढांचे की मान्यताओं से उसी प्रकार के समूह प्राप्त नहीं किये जा सकते। इन अप्रत्यक्ष लघु अर्थशास्त्रीय मान्यताओं और मॉडल में व्यावहारिक संबंधों की निरन्तरता, अतएव, केवल एक ऊपरी स्तर पर ही मानी जाती है। यदि एक समष्टिगत आर्थिक मॉडल में मान्यताओं की निरन्तरता पर कड़ी रोक लगानी हो, तो यह आवश्यक हो जाता है कि अर्थव्यवस्था की लघु अर्थव्यवस्था संरचना के विषय में मान्यताओं के मॉडल में एक ही समूह से प्राप्त व्यावहारिक समीकरणों को स्पष्ट रूप में प्राप्त किया जाए। इसमें सभी समष्टिगत आर्थिक मॉडलों में स्पष्ट लघु आधारों को समाहित किया जाना शामिल होगा।

¹ William J. Baumol (1952) "The Transaction Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach," *Quarterly Journal of Economics*, v.66, pp.545-66; James Tobin (1956) "The Interest-Elasticity of the Transactions Demand for Cash," *Review of Economics and Statistics*, v.38, pp.241-47; James Tobin (1958) "Liquidity Preference as Behavior Towards Risk," *Review of Economic Studies*, v.25, pp.65-86.

6.3.2 विवेकपूर्ण प्रत्याशाएं एवं नीति नियम

मान लें हमारे पास लघुआधारों से युक्त एक समष्टिगत आर्थिक मॉडल है। हम जानते हैं कि किसी भी निश्चित लघुआधारों के समूह के अन्तर्गत यह तथ्य निहित होना जरूरी है कि आर्थिक एजेंट अपने निजी निर्णय न केवल नीति सम्बन्धी चरों के वर्तमान मूल्यों के वरन् उनके अनुमानित भावी मूल्यों के आधार पर भी लेते हैं। नीतिगत चर के एक निश्चित वर्तमान मूल्य को चुनने के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाने के लिए यह निश्चय करना जरूरी है कि इस प्रकार के चुनाव का चर के भावी अनुमानित मूल्यों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा। हम इस बात पर पहले ही विचार कर चुके हैं कि किस प्रकार, नीति निर्माता के व्यक्तिपरक निर्णयों पर अर्थशास्त्रीय पूर्वानुमानों की निर्भरता को कम करने के लिए समष्टिगत आर्थिक मॉडल सामान्यतः यह मानते हैं कि आर्थिक एजेंटों की विवेकपूर्ण प्रत्याशाएं होती हैं। परन्तु, विवेकपूर्ण प्रत्याशाओं का अर्थ है कि नीतिगत चर के भावी मूल्यों से जुड़ा एक वस्तुपरक संभाव्यता वितरण, जिसमें कम से कम इन वितरणों के अनुमानित मूल्य ज्ञात हैं।

अतएव, इस प्रकार के समष्टिगत मॉडल का प्रयोग करके नीति का मूल्यांकन करने के लिए, स्वयं नीति निर्माता को यह ज्ञात होना चाहिए कि नीतिगत चर का लक्षित अनुमानित भावी मूल्य क्या है। इसका अभिप्राय है कि स्वयं नीति निर्माता को नीतिगत चर के निश्चित मूल्य पता होने चाहिए, जो भविष्य में विभिन्न परिस्थितियों में नीति द्वारा जांचे जायेंगे। अतएव, वर्तमान समय में किसी निश्चित नीति को चुनने के प्रभावों के मूल्यांकन के लिए नीति निर्माता के मन में पहले से ही एक नीति नियम होना चाहिए। इस प्रकार, लघुआधारों से युक्त और विवेकपूर्ण प्रत्याशाओं की मान्यता वाले मॉडल में, एक निश्चित वर्तमान नीति के प्रभावों का मूल्यांकन संभव नहीं है, परन्तु केवल एक निश्चित नीति नियम के अंश के रूप में एक निश्चित वर्तमान नीति के प्रभावों का, मूल्यांकन संभव है।

उदाहरण के लिए, ऐसे मॉडल में, वर्तमान अवधि में मुद्रा आपूर्ति में एक निश्चित वृद्धि दर के प्रभाव का मूल्यांकन करना संभव नहीं होगा। तब, केवल चयन के प्रभाव का मूल्यांकन करना संभव होगा, उदाहरण के लिए, एक ऐसा नियम, जो वर्तमान तथा सभी उपयोगी भावी अवधियों में मुद्रा आपूर्ति की एक निश्चित दर वृद्धि को निर्धारित करता हो, या एक ऐसा नियम जो वर्तमान और भावी समयावधियों को शामिल करते हुए मुद्रा आपूर्ति का एक निश्चित मार्ग दर्शाता हो या एक ऐसा नियम जो विगत अवधि की मुद्रा स्फीति की दर और बेरोज़गारी की दर के कार्य रूप में मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि की दर को स्थापित करता हो।

6.3.3 कुछ अनिवार्यताएँ

लघु आधारों की आवश्यकता स्पष्ट रूप से समष्टिगत आर्थिक मॉडलों पर अतिरिक्त सीमाएं लागू कर देती है। समग्र चरों के बीज व्यवहारिक समीकरणों का केवल उस समूह का ही प्रयोग किया जा सकता है, जिस समूह का प्रत्येक अवयव अर्थव्यवस्था की लघु आर्थिक संरचना के विषय में समान मान्यताओं से प्राप्त किया गया हो। इससे पता चलता है कि मॉडलों का समूह जो दिये गये समय के किसी बिन्दु पर लघु आधारों से निर्मित किये जा सकते हैं काफी हद तक उस समय में अर्थशास्त्रियों के ज्ञान की सीमा पर निर्भर करते हैं। क्योंकि समष्टिगत आर्थिक मॉडल का प्रबन्धन, जिस सरलता से मॉडल की मान्यताओं को इच्छित अर्थ प्रदान करने के लिए तर्कपूर्ण ढंग से ढाला जा सकता है – भी एक वाँछनीय गुण है। इससे पता चलता है कि उन लघु आधारों की प्रकृति पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध होते हैं, जो किसी भी समय समष्टिगत आर्थिक मॉडलों में शामिल किए जा सकते हैं।

उपरोक्त सीमा का एक संभव परिणाम यह हो सकता है कि अर्थशास्त्रियों का विश्लेषण, सच्चाई से दूर, केवल लघु अर्थशास्त्रीय संरचना वाले मॉडलों तक ही सीमित रह जाए। ध्यान रहे कि एक मॉडल द्वारा सुझाए गए, संभावित नीति विकल्प और इन नीतियों का मूल्यांकन पूरी तरह से मॉडल की लघु अर्थशास्त्रीय संरचना द्वारा निर्धारित होता है। अतएव यदि ये मॉडल, पूर्वकाल की कुछ समय तक, वास्तविक अर्थव्यवस्था की कार्यविधि की सफलतापूर्वक नकल कर भी लें, तो भी मॉडल के नीति सम्बंधी निष्कर्ष, वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य में, गलत संकेत देने वाले हो सकते हैं। इसका अभिप्राय है कि लघु आधारों से युक्त समष्टिगत आर्थिक मॉडल की स्थापना यद्यपि एक लाभदायक कोशिश हो सकती है, परन्तु इस संभावना से भी सावधान रहना चाहिए कि वास्तविकता का सरलीकरण करते हुए, लघु आधार, वास्तविकता को स्वीकार न किए जा सकने की हद तक तोड़ मोड़ दें।

इसके अतिरिक्त, यद्यपि लघु आधार युक्त समष्टिगत आर्थिक मॉडल बदलती नीति व्यवस्था की समयावधियों में अधिक अच्छी तरह काम करते हैं, परन्तु एक ही नीति के प्रभाव क्षेत्र में, उनके अच्छी तरह काम करने का कोई कारण नहीं होता। इसके अलावा, यदि व्यक्तिपरक आर्थिक एजेंट नीति प्रभाव में परिवर्तनों या निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने के लिए जानकारी एकत्रित करने और उनका प्रयोग करने को कठिन पाते हैं, तो अनियन्त्रित नीति ('rules of thumb') लगभग संतोषकारी होते हैं। इसके अलावा कि वे उन प्रक्रियाओं का आश्रय लें जो एक ही नीति प्रभाव का सर्वाधिक उपयोग करने के लिए बनाई गई हैं। इस स्थिति में, जब तक नीति प्रभावों में हुए परिवर्तन प्रकृति में असंगत न हों, आर्थिक एजेंट इन परिवर्तनों को वर्तमान नीति और प्रत्याशित भावी नीति के सम्बन्ध में इस प्रभाव को नज़रअन्दाज़ कर देते हैं। इन परिस्थितियों में लुकास की समालोचना का महत्त्व समाप्त हो जाता है।

6.4 नियम बनाम स्वनिर्णय

हम पहले देख चुके हैं कि लघु आधारों और आर्थिक एजेंटों की विवेकपूर्ण प्रत्याशा की मान्यता से युक्त इन वैकल्पिक नीतियों में चुनाव, वैकल्पिक नीति नियमों के बीच चुनाव का रूप ले लेता है। परन्तु, किसी भी क्षण में, ये नियम एक ऐसी नीति के चयन का रूप ले लेते हैं, जो उस दिये क्षण पर सुपरिभाषित प्रक्रिया के आधार पर, सर्वोत्तम हों। आवश्यकता इस बात की है कि भावी नीति के उद्देश्य यथा संभव स्पष्ट हों ताकि नीति निर्माता स्वयं ही अर्थव्यवस्था के निजी आर्थिक एजेंटों (गृहस्थ, व व्यावसायिक फर्म) की भावी नीति से सम्बन्धित विवेकपूर्ण प्रत्याशाओं की सही परख कर सकें।

उदाहरण के लिए यदि मान लें कि एक सरकार द्वारा अपनी वर्तमान और भावी नीति के बीच किया जाने वाला चुनाव पूर्णतः इस बात पर निर्भर करता है कि अगले आम चुनावों में इन नीतियों का चुनाव सम्बन्धी संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सरकार पर यह बन्धन होता है कि कहीं इन नीतियों के परिणामस्वरूप आने वाले सालों में इसे अपने पद से वंचित न होना पड़े। इसके अलावा यह भी मान लें कि जनता को यह पता हो कि आने वाले वर्षों में सरकार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन वैकल्पिक नीतियों में से किस नीति श्रृंखला को सर्वोत्तम मानती है। इस स्थिति में, आने वाली घटनाओं के संदर्भ में, अर्थव्यवस्था के निजी अधिकर्ता विवेकपूर्ण रूप से यह प्रत्याशा करते हैं कि सरकार कुछ निश्चित नीति श्रृंखलाओं का पालन करे। यदि सम्बन्धित घटनाओं की संभावित श्रृंखलाओं से जुड़ा कोई वस्तुपरक संभाव्यता वितरण हो, तो अर्थव्यवस्था के निजी एजेंट भावी नीति श्रृंखला से सम्बन्धित एक वस्तुपरक संभाव्यता वितरण प्राप्त कर लेते हैं।

सबसे पहले यह ध्यान दें कि सरकारी क्रियाओं के लिए उपयोगी हर घटना की श्रृंखला को पहले से नहीं जाना जा सकता। इसलिए, एक नीति नियम को परिभाषित करते समय, पूर्णतया अज्ञात, घटनाओं के प्रति सरकार की विवेक पर आधारित क्रियाओं को विचार में नहीं लिया जाना चाहिए। जिस अवधि के लिए नीति नियमों की घोषणा की गई है, उस अवधि के ही अन्दर, उनमें संशोधन करना कठिन होता है क्योंकि नीति नियमों का विश्वासपूर्ण होना अनिवार्य है। भावी नीति के विषय में निजी आर्थिक एजेंटों की प्रत्याशाएं नीति निर्माताओं द्वारा घोषित नीति नियम के अनुरूप होंगी यदि उन्हें यह विश्वास हो कि सरकार भविष्य में इसी नियम का पालन करेगी। इसलिए सर्वसम्मति से हस्तक्षेप की मांग की स्थिति में भी सरकार द्वारा स्व: विवेक से किया गया कार्य नियमों से जितना दूर होगा, भविष्य में सरकार द्वारा घोषित की जाने वाली नीति नियमों की विश्वसनीयता उतनी ही कम होगी। इस प्रकार, जहाँ नीति में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो या यह ज्ञात होने पर भी कि घोषित नीति नियम कुछ गलत मान्यताओं के आधार पर निर्धारित हुए हैं, सरकार अज्ञात परिस्थितियों का सामना करते हुए भी घोषित नीति नियमों में संशोधन करने से हिचकिचा सकती है।

यहाँ यह भी ध्यान देना चाहिए कि उचित घटनाओं की संभावित श्रृंखला के साथ जनता से जुड़े वस्तुपरक संभाव्यता बंटन पाने के लिए और उपयोगी घटनाओं की वैकल्पिक श्रृंखलाओं के अनुरूप इच्छित नीति श्रृंखला जानने के लिए, इन वैकल्पिक श्रृंखलाओं का (बिना अधिक विशेषताओं का प्रयोग किए) और संक्षेप में सरलतापूर्वक परिभाषित होना आवश्यक है। अतएव, यदि नीति नियमों का पालन किया जाए तब सरकारी नीतियों के परिस्थितियों के अनुकूल होने अथवा अर्थव्यवस्था के विषय में गुणात्मक निर्णयों के अनुरूप होने की संभावना भी समाप्त हो जाती है।

जहाँ नीति नियमों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली लोचहीनता के अपने कुछ परिणाम हैं, कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि इस लोचहीनता के कुछ लाभ भी संभव हैं। इस विचार के प्रचारकों में मिल्टन फ्रीडमैन प्रमुख हैं। फ्रीडमैन के विचार में, सरकार को वर्तमान परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करने में स्वतन्त्रता प्रदान करना हानिकारक है क्योंकि सरकार अक्सर सीमित अवधि के राजनैतिक लाभों, जो संकीर्ण होते हैं, के लिए नीतियों का निर्धारण करके इस स्वनिर्णय का दुरुपयोग करती हैं। इसके अतिरिक्त, यह नीति-निर्माताओं को, हर अस्थायी या छोटी मोटी अव्यवस्था की प्रतिक्रिया में, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए उकसाता है। यदि हस्तक्षेप की आवश्यकता की पहचान करने और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके अन्तिम प्रभाव की जाँच के समय और विभिन्न वैकल्पिक नीतियों के प्रभावों के परिमाण और समय के बारे में अत्यधिक अनिश्चितता हो, तो, इन स्थितियों में, यह महँगी साबित हो सकती है। उदाहरण के लिए उपयुक्त नीति के निर्माण अथवा रचना के लिए, नीति के कार्यकारिणी और विधायी अनुमोदन के लिए तथा नयी नीति के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक मशीनरी में किये जाने वाले समायोजन के लिए भी समय की आवश्यकता पड़ती है जिससे समय अंतराल बढ़ सकता है। नीतियों के प्रभावों के साथ जुड़ी अनिश्चितता को देख कर, फ्रीडमैन सलाह देते हैं कि स्वनिर्णय (discretion) आधारित नीति विषयक क्रियाएँ स्वयं ही अर्थव्यवस्था में, अज्ञात हलचलों का स्रोत बन जाती हैं।

दायित्वों का पालन करने वाली सरकार द्वारा घोषित नीति नियम की विश्वसनीयता न केवल पूर्व अनुभवों पर निर्भर करती है वरन् सरकार की नीति नियम पूरी करने की भावी संभावनाओं के तर्कपूर्ण मूल्यांकन पर भी निर्भर करती है। इस दृष्टिकोण से, अर्थव्यवस्था में निजी एजेंटों की तरह, सरकारों के भी लक्ष्य होते हैं, जिन्हें वे नीति क्रिया के माध्यम

से प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। यदि हम एक नीति नियम को समय-संगत या प्रवैगिक रूप से संगत मान कर परिभाषित करते हैं कि दिए गए समय में से किसी भी क्षण पर नियम के आधार पर चुनी गयी नीतियाँ, उस समयावधि के शेष भाग के लिए सर्वाधिक उपयोगी हों। इसके लिए यह मानकर चलना होता है कि उस क्षण के पूर्व चुनी गयी नीतियाँ उपलब्ध हों और यह कल्पना की जाए कि भविष्य के हर क्षण पर, नीति को सदुपयोगिता के आधार पर चुना जाएगा। यदि सरकारों के पास भविष्य में, नीति बदलने का अधिकार हो, तब घोषित किए गये नीति नियम की विश्वनीयता समाप्त हो जाएगी। समय संगतता (time-consistency) की स्थिति में ऐसा नहीं होगा। यदि एक नीति नियम में समय-संगतता नहीं है, तो भविष्य में किसी भी समय, सरकार के लिए नियम द्वारा निर्धारित नीति का पालन करना उपयोगी नहीं होगा। तब उस समय बिन्दु पर उस नीति से विमुख होने पर सरकार का भी लाभ है।

यहाँ एक समस्या उत्पन्न हो सकती है कि नीति नियम पूरे समय आदर्शतम हो सकता है परंतु उसमें समय-संगतता न हो। फिन किडलैण्ड और एडवर्ड प्रैस्कॉट ने यह संभावना, 1977 में प्रकाशित एक शोधपत्र में प्रस्तुत की। किडलैण्ड और प्रैस्कॉट ने एक प्रसिद्ध उदाहरण में एक नीति के मामले पर विचार करते हुये अपने तर्क की व्याख्या बाढ़ से उत्पन्न आपदाओं से सुरक्षा में की। मान लें, सामाजिक रूप से इच्छित परिणाम यह हो कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में घर न बनाए जाएं, परन्तु यदि वहाँ पहले से घर बने हुए हों तो बाढ़ रोकने के महँगे तरीके, जिनमें बाँध और किनारे बनाना शामिल हैं, ही इच्छित उपाय होंगे।

यदि सरकार यह घोषणा करती है कि वह वर्तमान में गैर-आवासीय बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में कभी भी बाढ़ रोकने के उपाय नहीं करेगी और यदि निजी एजेंट यह विश्वास कर लें कि सरकार इस नीति का पालन करती रहेगी, तो कोई भी उस क्षेत्र में मकान नहीं बनाएगा। परन्तु विवेकशील एजेंट इस नीति को विश्वास योग्य नहीं पाएगा, क्योंकि वह जानता है कि यदि एक बार वह या अन्य उस क्षेत्र में निर्माण कर लेते हैं तो बाढ़ रोकने के उपाय करना सरकार के लिए अधिक उपयोगी रहेगा। इसलिए समाज को एक ऐसे आंशिक उपयोगी परिणाम को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि यदि निजी एजेंट बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में निर्माण करते हैं, तो सरकार को बाँध और किनारे बनवाने होंगे।

यदि हम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में निर्माण कार्य को रोकने के कानून को लागू करने की संभावनाओं को दूर कर दें, तो सरकार के पास नीति नियम को विश्वसनीय बनाने का (कि वह बाढ़ग्रस्त गैर-आवासीय क्षेत्र में कभी बाढ़ रोकने के उपाय नहीं करेगी) एक ही तरीका है कि किसी भी प्रकार वह उस नीति नियम को लम्बे समय तक लागू करने से स्वयं को जोड़ सके। सरकार को यह विश्वास दिलाने में भी सफल होना चाहिए कि भविष्य में यह कोई भी ऐसा नीति नियम अपनाने में समर्थ नहीं होगी जो भविष्य में इसके लिए उपयोगी हो। अतः इस मत के अनुसार यदि आदर्शतम नीति नियमों (optimal policy) की विश्वसनीयता को बनाए रखना है तब किसी भी समय स्वनिर्णय नीति की तुलना में नीति नियम न केवल परिणामों को आदर्शतम स्तर तक पहुंचाते हैं वरन् नीति निर्माण में स्वनिर्णय नीति के उपयोग की संभावना भी सीमित हो जाती है।

एक अन्य तरीका, जिससे सरकार स्वयं को किसी एक निश्चित नीति नियम से जोड़े रख सकती है, वह यह है कि भविष्य में कभी भी उस नियम के उल्लंघन को विधि (legislation) के द्वारा महँगा बना दिया जाए। परन्तु, अप्रत्याशित घटनाओं, जिनमें नियम विचलन अत्यन्त आवश्यक हो या यदि यह पाया जाए कि नियम निर्धारण में की गयी महत्त्वपूर्ण मान्यताएँ गलत हैं, तब इस विधि में संशोधन कर पाना कठिन एवं काफी समय लेने वाला हो सकता है। आपात स्थिति में स्वनिर्णय का उपयोग करते हुये, लोचशीलता

को खोये बिना आदर्शतम नीति नियम को विश्वसनीय बनाने का एक अन्य तरीका यह है कि सरकार इस नीति की जिम्मेदारी किसी ऐसी स्वायत्त संस्था को दे जिसके कार्य व लक्ष्य सरकार के कार्यों व लक्ष्यों से भिन्न हों। इस प्रकार, सरकार अक्सर मौद्रिक नीति को एक स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंक की जिम्मेदारी बना देती है, जिसके पीछे यह विचार होता है कि मुद्रा स्फीति की दर कम करने के लिए बनाई गई एक मौद्रिक नीति तब अधिक विश्वसनीय मानी जाती है जो ऐसे निवेशकों द्वारा चालित है, जो राजनेताओं की अपेक्षा मुद्रा स्फीति से कहीं अधिक प्रभावित होते हैं।

निस्सन्देह, कुछ राजनेताओं या राजनीतिक दलों को औरों की अपेक्षा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक समय लग सकता है। इस स्थिति में, जब तक वे सरकार में हैं, वे नीति नियमों के पालन करने वाले (दल) के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। हो सकता है कि आरम्भ में इन राजनेताओं या दलों को कुछ कीमत चुकानी पड़े (वे लोग जो सरकार से यह आशा लगाते हैं कि सरकार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बाढ़ रोकने के उपाय करेगी, और उस क्षेत्र में घर बना लेते हैं, उनके घर बाढ़ में बह जाएंगे) परन्तु लम्बे समय में, सामाजिक रूप से इच्छित परिणामों को लागू करने से उन्हें लाभ ही होगा। (जनता सरकार के गैर-आवासीय बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में कभी बाढ़ रोकने के उपाय न करने के अब तक के निर्णयों पर विश्वास कर सकेगी और ऐसे क्षेत्र में निर्माण नहीं करेगी।)

बोध प्रश्न 2

- 1) एक समय-संगत नीति का पालन करते हुये स्व निर्णय किस प्रकार एक नीति के आंशिक उपयोगी परिणामों को उत्पन्न करता है?

.....

- 2) नीति निर्माण में लघु आधारों को शामिल करने के पीछे क्या औचित्य है?

.....

6.5 सारांश

इस अध्याय में हमने दी हुई भावी आर्थिक वातावरण की अनिश्चित प्रकृति की अवस्था में नीति निर्धारण के विषय पर विचार किया है। अधिकांश स्थितियों में, हमने पूर्व आंकड़ों के आधार पर समष्टिगत आर्थिक मॉडल निर्माण का सहारा लिया है। परन्तु, इस प्रकार के मॉडल यह मानकर चलते हैं कि पूर्वकाल में प्रचलित व्यवहार उसी प्रकार भविष्य में भी चलता रहेगा। जब एक अर्थव्यवस्था संक्रमण की अवस्था में हो या पूर्व नीतियों की प्रकृति अस्थायी हो तब समष्टिगत आर्थिक मॉडल संभवतया विश्वसनीय परिणाम नहीं दे पाते। रॉबर्ट लुकास ने समष्टिगत आर्थिक मॉडल निर्माण की सीमाओं को उजागर किया, जिसे लुकास की समीक्षा के नाम से जाना जाता है।

एक अन्य विषय जो हमने इस इकाई में लिया है वह समष्टिगत आर्थिक मॉडलों में व्यष्टिगत अर्थशास्त्रीय आधारों की सार्थकता है। हमने केंस के उपभोग फलन के द्वारा व्यष्टिगत आर्थिक आधारों की व्याख्या की है। इसके अलावा, समष्टिगत आर्थिक मॉडलों को परिभाषित करते समय विवेकपूर्ण प्रत्याशाओं की भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

व्यवहार में नीति निर्धारण को निश्चित नियमों या प्रक्रियाओं पर आधारित होना चाहिए। परन्तु अज्ञात बदलावों के कारण नीति नियमों में सुधार की जरूरत पड़ सकती है, जो अधिक समय लेने वाली और महँगी हो सकती है। इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए, सरकार को यह जिम्मेदारी किसी स्वायत्त संस्था को दे देनी चाहिए। कुछ समय तक एक आंशिक उपयोगी नीति का पालन करने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता।

6.6 महत्त्वपूर्ण शब्द

अंतर्जात चर	— समीकरणों की व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित होने वाले चर
बहिर्जात चर	— मॉडल के बाहर दिये गये चर
लघु आधार	— वह प्रक्रिया जहाँ एक मॉडल का समष्टिगत-व्यवहार, व्यष्टिगत-व्यवहार पर आधारित है।
स्थायी आय	— वर्तमान आय का वह भाग जिसके दीर्घकाल में भी प्राप्त होने की आशा है।
विवेकपूर्ण प्रत्याशाएं	— यह परिकल्पना कि व्यक्तियों की प्रत्याशाएं कुल मिलाकर पक्षपात रहित हैं।

6.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

The classic reference for Section 6.2 is the original paper by Lucas:

Robert E. Lucas, Jr. (1976) "Econometric Policy Evaluation: A Critique," in Karl Brunner and Allan H. Meltzer (eds) *The Phillips Curve and Labor Markets*, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Vol.1. Amsterdam: North-Holland. Reprinted in Robert E. Lucas, Jr. (1981) *Studies in Business Cycle Theory*, Oxford: Basil Blackwell, pp.104–130.

See also Thomas J. Sargent (1980) "Rational Expectations and the Reconstruction of Macroeconomics," *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, 4(Summer). Reprinted in Preston J. Miller (ed.) *The Rational Expectations Revolution: Readings from the Front Line*, Cambridge, Mass.: The MIT Press, pp.31–39.

An important reference for Section 6.3 is:

Robert E. Lucas, Jr. (1980) "Methods and Problems in Business Cycle Theory," *Journal of Money, Credit and Banking*, 12(4, part 2). Reprinted in Robert E. Lucas, Jr. (1981) *Studies in Business Cycle Theory*, Oxford: Basil Blackwell, pp.271–296.

See also the discussion of Lucas' paper by Edwin Burmeister and James Tobin in the same issue of *Journal of Money, Credit and Banking* and Sargent's paper cited above.

A critical overview of the endeavour to introduce microfoundations is provided by:

Kevin D. Hoover (2001) *The Methodology of Empirical Macroeconomics*, Cambridge: Cambridge University Press, Chapter 3.

For Section 6.4, refer to:

Milton Friedman (1948) "A Monetary and Fiscal Framework for Economic Stabilization," *American Economic Review*, 38, pp.245–64.

F. E. Kydland and E. C. Prescott (1977) "Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans," *Journal of Political Economy*, 85(3), pp.473–92.

David Romer (1996) *Advanced Macroeconomics*, Singapore: McGraw-Hill, Chapter 9.

6.8 बोध प्रश्नों के उत्तर/संकेत

बोध प्रश्न 1

- 1) हमने 6.2 में आय निर्धारण के सामान्य मॉडल को प्रस्तुत किया है। आप किसी अन्य उदाहरण के बारे में सोचें।
- 2) अनुभाग 6.2 में विशेषकर पृष्ठ संख्या 28 और 29 का अध्ययन करें।

बोध प्रश्न 2

- 1) अनुभाग 6.4 का अध्ययन करें और उत्तर जानें।
- 2) उप-अनुभाग 6.3.1 का अध्ययन करें और उत्तर जानें।